



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]
No. 45]

नई दिल्ली, बुध्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

सकल्प

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल, 1984

विषय: दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास
योजनाओं को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार
प्राप्त बोर्ड का पुनर्स्थापन।

सं० के० 14011/1/84-यू० डी० IVए—दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं को बनाने तथा उनके कार्या-
न्वयन के लिए जिस उच्चाधिकार बोर्ड को स्वास्थ्य मंत्रालय के 31 जुलाई,
1961 के संकल्प संख्या एफ 10/79/60-एल० एस० जी० द्वारा गठित
किया गया था तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के 31 मई, 1973 के
संकल्प संख्या-8-6 (1)/69-यू० डी०-II द्वारा पुनर्गठित किया गया था,
को एतद्द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा
दिल्ली के सभी वर्तमान भू-उपयोग प्रस्तावों तथा विकास योजनाओं पर
विचार करने का कार्य सीपा गया है जिसमें कि सभी अधिसूचना, सेवा,
परिवहन प्रणाली, रोजगार, आवास तथा सामान्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र के साथ विशेष रूप से दिल्ली महानगर क्षेत्र के भू-उपयोग जैसे तात्का-
लिक कार्य शामिल हैं। जब तक प्रस्तावित सांविधिक निकाय का गठन
किया जाता है तब तक यह उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड वही कार्य करेगा जो
कि बाद में प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण करेगा। इस पुनर्गठित उच्चा-
धिकार प्राप्त बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से है:—

1. केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री

अध्यक्ष

2. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

सदस्य

3. मुख्य मंत्री, हरियाणा

सदस्य

4. मुख्य मंत्री, राजस्थान

सदस्य

5. उप राज्यपाल, दिल्ली

सदस्य

6. केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मंत्री

सदस्य

7. निर्माण और आवास उप मंत्री

सदस्य

8. केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

सदस्य

9. केन्द्रीय मिर्चाई तथा ऊर्जा राज्य मंत्री

सदस्य

10. केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री

सदस्य

11. केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री

सदस्य

12. केन्द्रीय रेल अप मंत्री

सदस्य

13. मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद

सदस्य

14. महापौर, दिल्ली; दिल्ली नगर निगम

सदस्य

15. संयुक्त सचिव (यू डी)

निर्माण और आवास मंत्रालय

सदस्य सचिव

2. इस बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:—

(i) यह सुनिश्चित करना कि महानगर क्षेत्र के लिए (रिज
टाउनों सहित) और यदि आवश्यक हो, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र के लिए भी, प्रत्येक सहयोगी सरकारों के
प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन अधिकारों के माध्यम से समन्वित
तकनीकें तैयार किए जाएं;

(ii) जरणबद्ध तथा एककृत, आधार पर योजनाएं तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त विधियों का प्रावधान सुनिश्चित करना ताकि योजना या नक्शों में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर समस्त क्षेत्र का संतुलित विकास किया जा सके;

(iii) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों का मार्गनिर्देशन करना; और

(iv) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना जो कि विभिन्न योजना अभिकरणों में परिवर्तनीय आवश्यकता एवं परिस्थिति के मुताबिक भ्रमण-भ्रमण क्षेत्रों में योजना में संशोधन करने के लिए समय-समय पर प्राप्त होते हैं।

भ्रादेश है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी संबंधित सदस्यों को भेजी जाए।

भ्रादेश है कि संकल्प भारत के प्रसाधारण राजपत्र में जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

एल० एम० मैनेजिज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

RESOLUTION

New Delhi, the 6th April, 1984

SUBJECT :— High Powered Board for the formulation and the implementation of the development plans for the Delhi Metropolitan Area and the National Capital Region—Revival cf.

No. K. 14011/1/84-UDIVA:—The High Powered Board for the formulation and implementation of the development plans of the Delhi Metropolitan Area and the National Capital Region which was constituted *vide* Ministry of Health Resolution No. F. 10/79/60-LSG, dated the 31st July, 1961 and reconstituted *vide* the Ministry of Works & Housing Resolution No. 8—6/69-UD-II, dated 31st May, 1973 is hereby revived and entrusted with the task of examining all current land use proposals and development plans of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi which have an immediate bearing of the total infra-structure, service transportation pattern, employment, housing and land use of the National Capital Region area in general and Delhi Metropolitan Area, in particular. Till such time as the proposed statutory body comes into being, the High Powered Board would exercise the same functions as would be exercised later by the proposed statutory authority. The composition of the reconstituted High Powered Board is as follows :—

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Union Minister for Works & Housing | Chairman |
| 2. Chief Minister of Uttar Pradesh | Member |
| 3. Chief Minister of Haryana | |

- | | |
|---|------------------|
| 4. Chief Minister of Rajasthan | Member |
| 5. Lt. Governor of Delhi | „ |
| 6. Union Minister of Shipping and Transport | „ |
| 7. Deputy Minister for Works & Housing | „ |
| 8. Union Minister of State for Home Affairs and Power | „ |
| | „ |
| 10. Union Minister of State for Planning | „ |
| 11. Union Minister of State for Communications | „ |
| 12. Union Deputy Minister for Railways | „ |
| 13. Chief Executive Councillor, Delhi, Metropolitan Council | „ |
| 14. Mayor of Delhi, Municipal Corporation Delhi | „ |
| 15. Joint Secretary (UD) Ministry of Works & Housing | Member Secretary |

2. The terms of reference of the Board will be as under:—

- (i) to ensure that coordinated plans are prepared for the Metropolitan Region (including the ring towns) and if necessary also for the National Capital Region through the agencies under the administrative control of each of the Governments participating;
- (ii) to ensure the provision of adequate funds for the preparation and implementation of the plans on a phased and integrated basis so that the development is balanced over the whole area on the basis of the accepted proposals in the plan or plans;
- (iii) to guide the various agencies for the implementation of the plans in the different areas;
- (iv) to consider any proposals that may come up from time to time from the various planning agencies in the different areas for the modification of the plan according to changing needs and circumstances.

ORDER : Ordered that a copy of the Resolution be communicated, to all concerned.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extra-Ordinary for general information.

L.M. MENEZES, Jt. Secy. (UD)